भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3585

11.08.2025 को उत्तर के लिए

राष्ट्रीय तटीय योजना

3585. श्री वाई. एस. अविनाश रेड्डीः

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) राष्ट्रीय तटीय योजना के बाह्य सहायता प्राप्त घटक और गैर-बाह्य सहायता प्राप्त घटक के अंतर्गत आन्ध्र प्रदेश को प्रदान की गई निधियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान आन्ध्र प्रदेश राज्य में उक्त योजना के अंतर्गत कार्यान्वयन हेतु कितनी परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है;

(ग) विगत पांच वर्षों के दौरान इन परियोजनाओं की प्रगति और प्रस्तुत किए गए उपयोग प्रमाणपत्रों का वर्ष-बार ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या आन्ध्र प्रदेश राज्य में उक्त योजना के अंतर्गत नई परियोजनाएं कार्यान्वित की जाएंगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री :
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (घ): राष्ट्रीय तटीय प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रीय तटीय मिशन (एनसीएम) एक केन्द्रीय क्षेत्र योजना है जिसके निम्नलिखित घटक हैं:

i. मैंग्रोव और प्रवाल भित्तियों के संरक्षण संबंधी प्रबंधन कार्य योजना
ii. समुद्री और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र में अनुसंधान एवं विकास
iii. समुद्र तट पर्यावरण एवं सौंदर्य प्रबंधन प्रणाली के अंतर्गत समुद्र तटों का संधारणीय विकास
iv. समुद्र तट सफाई अभियान सहित समुद्री और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के संबंध में तटीय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का क्षमता निर्माण/आउटरीच कार्यक्रम।

एनसीएम की कार्यान्वयन एजेंसियाँ तटीय राज्यों की राज्य सरकारें और संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) प्रशासन हैं। इस मंत्रालय में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर तटीय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधि जारी की जाती है।

विशाखापत्तनम के रुशिकोंडा बीच के लिए पर्यावरण के अनुकूल समुद्र तट अवसंरचना और प्रबंधन सुविधाओं के विकास हेतु वित्त वर्ष 2020-21 में ₹2.22 करोड़ की राशि प्रदान की गई। रुशिकोंडा बीच को वर्ष 2020 से ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त है।

इसके अलावा, एनसीएम के तहत वित्त वर्ष 2023-24 और वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान रामकृष्ण समुद्र तट और नंदामुरी तारक रामाराव समुद्र तट पर समुद्र तट की सफाई एवं जागरूकता अभियान के लिए कुल 2.6 लाख रुपये की राशि प्रदान की गई। जारी की गई सभी धन राशि के लिए उपयोग प्रमाण पत्र प्राप्त हो चुके हैं।

इस मंत्रालय को आंध्र प्रदेश राज्य से एनसीएम के अंतर्गत कोई नया प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

*****